**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 519**

**दिनांक 03 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न**

**डेयरी किसानों और पशुपालकों की आवश्यकता का आकलन**

**519. डॉ. कडियम काव्यः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चारा उपलब्धता, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशुधन रोग नियंत्रण सहित डेयरी किसानों और पशुपालकों की जरूरतों का आकलन किया है;

(ख) क्या वारंगल जिले में सचल पशु चिकित्सा इकाई (एमवीयू), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनडीडीपी), राष्ट्रीय गोकुल मिशन और पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के अंतर्गत कितने गांवों को कवर किया गया है, पशु चिकित्सा सेवा प्रदान की गई है तथा कितने पशुओं का टीकाकरण किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा समुचित और समय पर दूध खरीद भुगतान सुनिश्चित करने, प्रशीतन/प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वारंगल में डेयरी किसानों के लिए रोग से संबंधित नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क)से (घ) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग राज्यों से प्राप्त कार्य योजनाओं के आधार पर योजनाएँ बना रहा है और उन्हें कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं तेलंगाना के वारंगल संसदीय क्षेत्र सहित देश भर के सभी जिलों और गाँवों को कवर कर रही हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, पशु रोगों पर नियंत्रण रखने, दूध प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और पशुधन बीमा कवरेज को बढ़ाने के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित योजनाएं और उपाय कार्यान्वित कर रही है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए RGM को कार्यान्वित किया जा रहा है, इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रमुख पहलें की जा रही हैं:

(i) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य AI कवरेज को बढ़ाना और देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता  वाले सांडों के सीमन के साथ किसानों के घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना है। अब तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9.54 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 14.99 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 5.69 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में 35.55 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 49.15 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 17.57 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और वारंगल जिले में 92104 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है, 1.23 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 57103 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ii) सेक्स-सॉर्टेड सीमन: 90% तक सटीकता के साथ बछड़ियों का जन्म सुनिश्चित करने के लिए देश में सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक शुरू की गई है। देशी रूप से तैयार सेक्स-सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक प्रारंभ कर दी गई है और इस तकनीक के कारण सेक्स-सॉर्टेड सीमन की लागत उल्लेखनीय रुप से कम हुई है और किसानों को उचित दरों पर सेक्स-सॉर्टेड सीमन उपलब्ध है। अब तक, देशी नस्लों के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों का उपयोग करके 1.34 करोड़ सेक्स सॉर्टेड सीमन खुराक तैयार की जा चुकी हैं।

(iii) सेक्स सॉर्टेड सीमन बढ़ावा देने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है और किसानों को सुनिश्चित गर्भधारण पर सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत के 50% तक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

(iv) ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITRI's): किसानों के घर-द्वार पर ही गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए मैत्री (MAITRI's) को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जा रहा है। अब तक, देश में 39810 मैत्री प्रशिक्षित और शामिल किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान तेलंगाना में 258 मैत्री शामिल किए गए हैं।

(v) देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से विभाग ने भारत भर में 24 IVF प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। IVF तकनीक का लाभ उठाते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य उन्नत प्रजनन पद्धतियों को किसानों तक पहुंचाना है। प्रत्येक सुनिश्चित गर्भधारण पर 5,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है। इन प्रयोगशालाओं से 28358 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए गए हैं, जिनमें से, 16065 भ्रूण अंतरित किए गए हैं और 2593 बछड़े-बछड़ियां पैदा हुए हैं। देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं के प्रसार के लिए विभाग ने तेलंगाना में 1 IVF प्रयोगशाला स्थापित की है और इसके द्वारा 435 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए हैं, जिनमें से 350 भ्रूण अंतरित किए गए हैं और 15 बछड़े-बछड़ियां पैदा हुए हैं।

(vi) देशी नस्ल के सांडों सहित उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उत्पादन के लिए संतति परीक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। संतति परीक्षण गोपशुओं की गिर और साहीवाल नस्ल तथा भैंसों की मुर्रा और मेहसाना नस्ल के लिए क्रियान्वित किया गया है। वंशावली चयन कार्यक्रम के अंतर्गत गोपशु की राठी, थारपारकर, हरियाना और कांकरेज नस्ल तथा भैंस की जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल कवर की गई हैं। अब तक 4466 उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता  वाले सांड उत्पादित किए गए हैं और सीमन उत्पादन के लिए सीमन केंद्रों को उपलब्ध कराए गए हैं।

(vii) देशी नस्ल के सीमन सहित सीमन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए सीमन केंद्रों को सुदृढ़ बनाना। अब तक 47 सीमन केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्वीकृत किया जा चुका है। करीमनगर और कसमपल्ली में स्थित 2 सीमन केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए तेलंगाना को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(viii) किसानों में जागरूकता पैदा करना: इस योजना के अंतर्गत, देशी बोवाइन नस्लों के महत्व के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिताएं, बछड़ा- बछिया रैलियां, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): NPDD को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया गया है:

(i) NPDD का घटक ''क'' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/ जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों/ स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/ दूध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरण के लिए अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) NPDD योजना का घटक ''ख'' "सहकारिताओं के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना के उन्नयन और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और दूध उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) योजना के घटक 'क' के अंतर्गत 2153.60 लाख रुपये और घटक ख के अंतर्गत 7429.99 लाख रु.(6491.91 लाख रुपये ऋण के तौर पर और 938.08 लाख अनुदान के तौर पर जारी किए हैं।

3. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO): गंभीर प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से उबरने के लिए राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता करना। दिनांक 15.12.2025 तक, तेलंगाना में, 2 दूध संघों के लिए 150 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजीगत ऋण का लाभ उठाते हुए 65.15 लाख रुपये (नियमित ब्याज सबवेंशन के रूप में 39.03 लाख रुपये और अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के रूप में 26.12 लाख रुपये) जारी किए गए हैं।

4. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): (AHIDF) पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त हो सके।

5. भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना में निम्नलिखित तीन उप-मिशन शामिल हैं: (क) पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन; (ख) पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन; और (ग) नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन।

पशु आहार और चारा संबंधी उप-मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:

(i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता
(ii) पशु आहार और चारा में उद्यमशीलता कार्यकलाप
(iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा बीज भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमी तैयार करना
(iv) गैर-वन बंजर भूमि/रेंजभूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन और वन भूमि से चारा उत्पादन

भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, चारा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना में सहयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य चारा उत्पादों - साइलेज, हे, सूखे चारे के ब्लॉक, संपूर्ण मिश्रित राशन (टीएमआर), प्लांटिंग सामग्री, चारा बीज आदि के उत्पादन और बिक्री की संगठित प्रणाली विकसित करना और देश में चारे की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना है। अब तक 100 FPOs पंजीकृत हो चुके हैं।

पशुधन बीमा कार्यक्रम: पशुओं के बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम के हिस्से के रूप में राज्य सरकार को 60:40 या 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी प्रीमियम का 15% हिस्सा प्रदान करता है। सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार भेड़ और बकरी के लिए 10 गोपशु इकाइयों तक और सूअर और खरगोश के लिए 5 पशु इकाइयों तक सीमित है (1 पशु इकाई = 10 भेड़/बकरी/सूअर/खरगोश)। जोखिम प्रबंधन और बीमा देश के सभी जिलों में कार्यान्वित है। देशी/संकरित दुधारू पशु, भार ढोने वाले पशु (घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, टट्टू और गोपशु/ नर भैंस) तथा अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक और मिथुन आदि) इस कार्यकलाप के दायरे में आते हैं।

6. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP): पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण संबंधी व्यवस्था करना पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना। साथ ही, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण बनेगा। अब तक, तेलंगाना में FMD के लिए 3.58 करोड़ और ब्रुसेलोसिस के लिए 7.49 लाख टीकाकरण किए जा चुके हैं।

इस योजना के तहत तेलंगाना में 100 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVU) की स्थापना के लिए निधियां संस्वीकृत की गई हैं। हालांकि, राज्य ने यह निधियां भारत सरकार को वापस कर दी हैं। इसलिए, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में इस योजना के तहत कोई भी एमवीयू कार्यरत नहीं है।

केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना को उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

अनुबंध-I

केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना राज्य को जारी की गई निधियों का विवरण।

| क्र. सं. | योजनाओं के नाम | पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय गोकुल मिशन | 5795.39 |
| 2 | राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) | 9583.59 |
| 3 | डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता | 65.15 |
| 4 | राष्ट्रीय पशुधन मिशन | 1820.87 |
| 5 | पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) | 6119.18 |